EMBARGOED FOR RELEASE: 06:00 AM (IST), MONDAY, 17 JANUARY 2022

सबसे अमीर 98 भारतीयों के पास उतनी ही संपत्ति है जितनी निचले तबके के 55.2 करोड़ लोगो के पास

भारत के 98 सबसे अमीर अरबपति परिवारों पर अगर एक प्रतिशत संपत्ति कर लगाया जाये तो इससे आयुष्मान भारत- भारत सरकार के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वस्थ्य बीमा कोष के लिए सात वर्ष से भी अधिक अवधि तक के लिए जरूरी राशि की प्रतिपूर्ति हो सकती है।

नई दिल्ली 17 जनवरी 2021: ऑक्सफैम इंडिया की नवीनतम ब्रीफिंग **'इनईक्यूलिटी किल्स'** से यह पता चलता है के पिछले एक वर्ष में जब देश में 84 प्रतिशत परिवारों को जीवन और आजीविका के क्षति के कारण अपनी आय में गिरावट का सामना करना पड़ा उसी समय भारत में अरबपतियों कि संख्या 102 से बढ़ कर 142 हो गयी। विश्व आर्थिक मंच के "दावोस एजेंडा " के पहले आज इस रिपोर्ट को ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी किया गया है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगो की सामूहिक संपत्ति वर्ष 2021 में 57.3 लाख करोड़ (775 अरब डॉलर) के उच्चस्तर तक पहुंच गयी।

अमिताभ बेहर सी0इ0ओ, ऑक्सफैम इंडिया ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि "ऑक्सफैम की वैश्विक रिपोर्ट" असमानता की कठोर वास्तविकता के ओर इशारा करती है जो प्रत्येक दिन कम से कम 21,000 लोग या हर चार सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु में योगदान करती है। कोरोना महामारी ने लैंगिक समानता को 99 साल से 135 साल पीछे ढकेल दिया है। महिलाओं की सामूहिक कमाई में वर्ष 2020 में 59.11 लाख करोड़ (800 अरब डॉलर) का नुकसान हुआ है जहाँ कि वर्ष 2019 की तुलना में 1.3 करोड़ कम महिलायें अब कार्यरत हैं। भयावह गैरबराबरी पर प्रहार करते हुये अति-धनी व्यक्तियों पर अमीरी-कर लगाते हुये गैरबराबरी की स्थिति को सही करते हुये वास्तविक अर्थव्यस्था में लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिये उनसे धन वापसी की दिशा में कभी भी प्राथमिकता नहीं रही है।

भारत में, महामारी के दौरान (मार्च 2020 से 30 नवंबर, 2021 तक) अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपये (313 अरब डॉलर) से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपये (719 अरब डॉलर) हो गई। इस बीच 4.6 करोड़ से अधिक भारतीयों के 2020 में अत्यधिक गरीबी में जाने का अनुमान है (संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व स्तर पर नए गरीबों के आंकड़े का लगभग आधा)। भारत में गरीब एवं अभिवंचितों के हितों की तुलना में अति-अमीर को बढ़ावा देने वाली चालाकी से संचालित अर्थ-व्यवस्था से हीं भयावह आर्थिक असमानता की स्थिति उत्पन्न हुयी है।

गैर-बराबरी से जूझने के लिए जरूरी कदम जैसे कि स्कूली शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी में ज्यादा आवंटन, मातृत्व अवकाश, भुगतान अवकाश और सभी भारतीयों के लिए पेंशन आदि के लिए 10 प्रतिशत सबसे अमीरों पर एक प्रतिशत अधिभार की पैरोकारी करता है।

ऑक्सफैम इंडिया के सी0इ0ओ0 अमिताभ बेहर नें बताया कि, "**इनइक्यूलिटि किल्स"** रिपोर्ट यह दर्शाता है कि हमारी आर्थिक प्रणाली कितनी ज्यादा असमान है। यह न केवल असमानता बल्कि गरीबी को भी बढ़ावा देती है। हम भारत सरकार से एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिये प्रतिबद्ध करने की मांग करते हैं जी कि ज्यादा समान एवं आत्म-निर्भर देश का निर्माण करे। भारत दुनिया को दिखा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं धन के पुनर्वितरण और समावेशी विकास के लिए सक्षम हैं जहां कोई भी विकास से छूटता नहीं। असमानता और गरीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई को उन अरबपतियों को समर्थन करना चाहिए जिन्होंने महामारी के दौरान देश में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया।

अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता

ऐतिहासिक रूप से, भारत हमेशा अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर रहा है। वर्ष 2000 में कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर का प्रतिशत 63.69 प्रतिशत था। अफसोस की बात है कि महामारी के दौरान भी यही सिलसिला जारी रहा जहांकि सरकारी राजस्व, अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर रहा - खास तौर पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और निर्माण पर लगाया जाने वाला कर, जिस पर आम भारतीय निर्भर हैं।

ऑक्सफैम इंडिया का रिपोर्ट इस को दर्शाता है कि केंद्र सरकार के राजस्व के हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष कर ऐसे समय में भी बढ़ रहा है जब पिछले चार वर्षों में कॉर्पोरेट कर के अनुपात में गिरावट आई है। 2020-21 के पहले छः महीने में पिछले वर्ष की तुलना में ईंधन पर 33 प्रतिशत ज्यादा कर की बढ़ोतरी की गयी जो कि कोरोना के पहले कि अवधि से 79 प्रतिशत ज्यादा है।

वहीं, वर्ष 2016 में अमीरो के संपत्ति पर लगाये जाने वाले संपत्ति कर को समाप्त कर दिया गया। पिछले साल निवेश को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट करों को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इससे देश के राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुयी है। यह प्रवृत्ति इस बात को दर्शाता हैं कि गरीब, अभिवंचित एवं मध्यमवर्गीय नें महामारी से जूझने के साथ ज्यादा कर अदा किया है। जबकि अमीरों नें महामारी के दौरान में अपने हिस्से का भुगतान नहीं करने के साथ अपने धन में अपर बढ़ोतरी की।

दशकों से सार्वजनिक सेवाओं के लिये कम आर्थिक आवंटन

ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि समान राजस्व उत्पन्न करने में विफलता के साथ केंद्र सरकार के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं के लिये प्राथमिकता कि कमी रही जबकि ये दो मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिये ज्यादा जरूरी थी।

केंद्र सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य के लिये बजट के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की कमी हुई जबकि 2021-22 में शिक्षा के लिए आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर किए जाने वाला खर्च 1.2 से 1.6 प्रतिशत पर बेहद कम रहा है जोकि पिछले 22 वर्षों में मात्र 0.09 प्रतिशत के दर से हीं बढ़ा। इसी तरह, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा खर्च 3 प्रतिशत तक हीं कम रहा है जोकि पिछले 18 वर्षों में मात्र 0.07 प्रतिशत तक हीं बढ़ा।

श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर व्यय (श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की केंद्र प्रायोजित योजना 2021-22 में कुल खर्च मात्र 0.6 प्रतिशत हीं है जोकि पिछले वर्ष के कुल खर्च की तुलना में 1.5 प्रतिशत कम है। असंगठित क्षेत्र के कार्य जो कि देश के कुल कार्यबल का 93 प्रतिशत है को संगठित कार्य श्रेणी के दायरे में लाने कि दिशा में बहुत कम सफलता मिली है जिससे कि उन्हें मूलभूत सामाजिक सुरक्षा जैसे कि सवेतन अवकाश, स्वास्थ्य बीमा, सवैतनिक मातृत्व अवकाश और पेंशन जैसे विभिन्न लाभ मिल सके।

बुनियादी सेवाओं का निजीकरण समानता के लिए घातक

भारत में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के निजीकरण की दिशा में नीतिगत ज़ोर असमानता को और बढ़ावा देता है। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा 2021 में किए गए सर्वेक्षण द्वारा इस बात का पता चला कि 52 प्रतिशत माता-पिता जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं उनके बच्चों के फीस में वर्ष 2021-22 में बढ़ोतरी हुयी। 35 प्रतिशत बच्चों को फीस न देने के कारण शिक्षा ग्रहण करने से रोक दिया गया। 38 प्रतिशत माता-पिता को प्रवेश के समय अवैध रूप से कैपिटेशन फीस देना पड़ा और 57 प्रतिशत माता-पिता को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ा जो कि घोषित आधिकारिक फीस ब्रेक-अप का हिस्सा नहीं था। सर्वेक्षण से इस बात का पता चलता है कि अभिभावकों को अपनी घरेलू आय का एक बड़ा हिस्सा (15% या उससे अधिक) निजी स्कूल की फीस पर खर्च करते हैं। स्कूली शिक्षा का बढ़ता निजीकरण देश के गरीब और हाशिए के लोगों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को असमान रूप से प्रभावित करता है।

ऑक्सफैम इंडिया की ब्रीफिंग से पता चलता है कि निजी स्वास्थ्य के लिये बढ़ा हुया खर्च हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित कर रही है खास कर बढ़े हुये स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च के द्वारा गैर-बराबरी और बढ़ी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन0एस0एस0) (2017-18) के आंकड़ों से पता चलता है कि निजी अस्पतालों में अतिरिक्त स्वास्थय सुविधा खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय सार्वजनिक अस्पतालों में अन्तः रोगी (इनपेशेंट देखभाल) से लगभग छह गुना है। और वाह्य रोगी देखभाल पर होने वाले खर्च से दो से तीन गुना अधिक है। भारत में औसतन अतिरिक्त स्वास्थय सुविधा खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय) 62.67% है जबकि वैश्विक स्तर पर यह औसतन 18.12% है।

भारत में असमानता से लड़ने के लिए बढ़ता समर्थन

देश भर के राजनेता, सरकारें, नागरिक समाज, शिक्षाविद और नौकरशाह पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक असमान, इसके दुष्प्रभावों एवं इससे निबटने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर बार-बार जोर दे रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने अक्टूबर 2019 में कहा था कि, "हर जगह असमानता बहुत बढ़ गई है"। बनर्जी ने जनवरी 2020 में भारत में संपत्ति कर को फिर से शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि, "अब असमानता की मात्रा को देखते हुए, संपत्ति कर पूरी तरह से समझदारी भरा कदम है। और धन के पुनर्वितरण की अधिक आवश्यकता है"।

अगस्त 2019 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर0एस0एस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि, "जबरदस्त आर्थिक प्रगति के बावजूद, दुनिया की संपत्ति कुछ लोगों द्वारा नियंत्रित की जा रही है।"

15 अगस्त 2021 को, केरल के मुख्यमंत्री, पिनाराई विजयन ने कहा कि, "एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, हमने कई चीजें हासिल की हैं। अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। देश में आर्थिक और सामाजिक असमानताएं बहुत प्रबल रूप से विद्यमान हैं।" गरीबी अभी भी मिटी नहीं है "।

दिसंबर 2021 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई0एस0 जगन मोहन रेड्डी ने आय असमानता को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि इससे ग्रामीणों के कर्ज में बढ़ोतरी होगी, क्रय शक्ति कम होगी और इससे ग्रामीण समग्र मांग में भी कमी आयेगी। परंतु हमे शब्दों से आगे बढ़ कर असमानता और गरीबी के चक्र को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यह बिलकुल संभव है अगर भारत सरकार अमीरों पर कर लगाये जिससे महामारी से उबरने के लिए बहुत जरूरी संसाधन एकत्र हो सके।

सिफ़ारिशे :

ऑक्सफैम इंडिया का मानना है कि निम्नलिखित सुझावों को लागू किया जाना चाहिये:

- **असमानता को वास्तविक रूप में मानना और इसे मापने के लिए सहमत होना :**भारत को अपने नीतिगत प्रभाव को मापने के तकनीक में सुधार करना चाहिये। आय से जुड़े सार्वजनिक आंकड़ों को तत्काल एकत्रित करने की आवश्यकता है। लगातार आय एवं आर्थिक गैर-बराबरी से सम्बंधित आंकडों को एकत्रित करने की शुरुवात की जानी चाहिये। साथ हीं यह सुनिश्चित किया जाए कि ये आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों। एक दशक में आय और आर्थिक गैर-बराबरी के आंकड़ों का तुलनात्मक प्रणाली से एकत्रित करते हुये कम से कम दो सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।

- **बहुसंख्यकों के लिए संसाधन सृजित करने के लिए भारत के धन को अति-अमीरों से पुनर्वितरित करें :**यह भारत के लिए महामारी से उबरने के लिए बहुत आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने के लिए वैल्थ कर को फिर से शुरू करने का समय है। भारत के गरीब और मध्यम वर्ग पर

अप्रत्यक्ष कर लगाने के बजाय अमीर व्यक्तियों द्वारा कर अनुपालन में भी काफी सुधार किया जाना चाहिए। साक्ष्य से पता चलता है कि ऑडिट का खतरा अनुपालन पर सबसे स्पष्ट प्रभाव दिखाता है और कर चोरों को शर्मसार करने या दंड लगाने से पूर्ण हो सकता है और प्रत्यक्ष कर दरों में कमी से नियमों के अनुपालन पर अस्पष्ट प्रभाव पड़ता है और राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

- **भविष्य की पीढ़ियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए राजस्व उत्पन्न करें :** सबसे अमीर 10 प्रतिशत आबादी पर एक अस्थायी एक प्रतिशत अधिभार अतिरिक्त INR 8.7 लाख करोड़ जुटाने में मदद कर सकता है, जिसका उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। महामारी का प्राथमिक परिणाम गुणवत्ता, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित और सार्वजनिक रूप से वितरित स्वास्थ्य प्रणाली होनी चाहिए जो सभी के लिए काम करती है न कि केवल अमीरों के लिए। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जो सभी की जरूरतों को पूरा करे, न कि केवल उन लोगों की जो कुलीन निजी स्कूलों में भाग लेने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं या जिनके पास डिजिटल तकनीक तक पहुंच है। भारत के रोगी अधिकार चार्टर को लागू करके, नैदानिक प्रक्रियाओं का मानकीकरण, ग्रामीण क्लीनिकों का निर्माण, और परिवार-स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाने के साथ सुव्यवस्थित स्वास्थ्य आई0टी0 सिस्टम विकसित करके, स्वास्थ्य सेवा में अधिक निवेश करके चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर कार्यरत अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण और भुगतान करना चाहिए ।

- **गैर-संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वैधानिक सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को लाना और लागू करना :** जबकि सरकार बड़ी संख्या में गिग अर्थव्यसथा के तहत संविदा (अस्थायी) श्रमिकों को मान्यता दे रही है, उसे भारत के 93 प्रतिशत कार्यबल के लिए बुनियादी सामाजिक क्षेत्र सुरक्षा के कानूनी आधार को तैयार करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

- **नियमों को बदलें और अर्थव्यवस्था और समाज में सत्ता को स्थानांतरित करें :**यह सामाजिक और आर्थिक नीतियों को उलटने का समय है, जिसके द्वारा भारत के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए निराशाजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं। यह सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण और व्यावसायीकरण को उलटने, बेरोजगारी में वृद्धि को संबोधित करने और भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपायों को वापस लाने का समय है।

संपादक के लिए नोट्स

विकास योजनाएं, जोकि भारत के अमीरों पर कर लगाकर बजट किया जा सकता है, निम्नवतहैं-

- 98 अरबपतियों की संपत्ति पर चार प्रतिशत टैक्स के द्वारा 17 साल तक देश मे मध्यायन भोजन कार्यक्रम को या समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम को 6 वर्ष तक चलाया जा सकता है।
- 98 सबसे अमीर अरबपति परिवारों पर एक प्रतिशत संपत्ति कर आयुष्मान भारत स्कीम को सात साल से अधिक समय तक वित्तपोषित करेगा।
- भारत के 98 अरबपतियों की संपत्ति पर एक प्रतिशत कर से स्कूली शिक्षा और साक्षरता पर होने वाले कुल खर्च का वहन किया जा सकता है।
- 98 अरबपतियों की संपत्ति पर चार प्रतिशत कर, मिशन पोषण 2.0 (आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना (को 10 वर्षों के लिए निधि देने के लिए पर्याप्त होगा।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए भारत का 2021 का बजट आवंटन भारत के अरबपतियों की सूची में सबसे निचले दस लोगों की कुल संचित संपत्ति के आधे से भी कम है। 10 करोड़ से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर केवल 2% कर मंत्रालय के बजट में आश्चर्यजनक रूप से 121% की वृद्धि कर सकता है।
- यदि पहले सौ अरबपतियों की संपत्ति जमा हो जाती है, तो वे अगले 365 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना को वित्तपोषित कर सकते हैं।

ऑक्सफैम इंडिया के बारे में :ऑक्सफैम इंडिया भेदभाव को खत्म करने और एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए काम कर रहे लोगों का एक आंदोलन है।